

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खालियर कैम रोवा ॥ न. प्र. ॥

विगयनी 157-III-15



13201-

856
29.12.14

श्रीनिवास तिवारी तय श्री रामगुलाम तिवारी निवासो ग्राम
बडेरा, तहसील मझगाँव जिला सतना म. प्र. -----पुनरोक्षकर्ता
बनाम.

इसिन म. प्र. जेरिए कलेक्टर सतना म. प्र. -----गेर पुनरोक्षकर्ता

श्री. नि. हा. पाठक एड
द्वारा आज दिनांक 29.12.14 के
प्रस्तुत किया गया।

M
जिडर
सर्किट कोर्ट रोवा

पुनरोक्ष विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
अपर आयुक्त महोदय संभाग रोवा- म.प्र.
द्वारा प्र. प्र. अंजोक्रत पुनस्थापना 113-14
आदेश दिनांक 03/11/14

क्रमांक 4228
सर्जिस्ट पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त.
12-1-15
सर्किट कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. खालियर

पुनरोक्ष अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. झ. रा.
संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

पुनरोक्ष के आधार निर्मांलौखत है :-

1:- यह कि अधोनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रोवा संभाग
रोवा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03-11-014 विधि व प्रक्रिया
के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

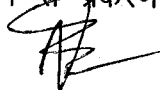
2:- यह कि अधोनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनरोक्षकर्ता द्वारा आवेदन अन्तर्गत
धारा 35 [3] म. प्र. झ. रा. राजस्व संहिता 1959 ई. के तहत पुनस्थापित किए
जाने खारिज प्र. क्रमांक 150/अमोल/08-09 आदेश दिनांक 4-03-09 दिया
गया था। परन्तु अधोनस्थ न्यायालय आवेदन पर ग्राह्य बिचार किए बिना

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-157-तीन/2015

जिला-सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-9-2015	<p>आवेदक की ओर से श्री चित्रेन्द्र पाठक अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया ।</p> <p>आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-150/अपील/08-09 में पारित आदेश दिनांक-4.3.2009 से प्रकरण में आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया गया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा प्रकरण को पुनर्स्थापित किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक-3.11.14 से निरस्त किया गया है जो उचित नहीं है । प्रकरण को निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर ग्राह्य करने का निवेदन किया गया है ।</p> <p>आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर भी विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी आदेश दिनांक-3.11.14 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हो रहे हैं कि आवेदक द्वारा धारा 35(3) आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत न कर 5 वर्ष के अप्रत्याशित बिलम्ब से प्रस्तुत किया गया है साथ ही इतने लम्बे बिलम्ब के कारणों को भी स्पष्ट नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक-3.11.14 में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों ।</p>	c
		 सदस्य